नेपाल के अध्ययन दल ने प्रोड्यूसर कम्पनियों की गतिविधियों में रुचि दर्शाई

❑ आर.बी. त्रिपाठी

मध्यप्रदेश भ्रमण पर आये नेपाल दल ने शिवपुरी जिले में स्व-सहायता समूहों से चर्चा की

नेपाल में विश्व बैंक की सहायता से संचालित गरीबी निवारण कोष के एक अध्ययन दल ने हाल ही में मध्यप्रदेश के चुने हुए जिलों में संचालित जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना डी.पी.आई.पी. की गतिविधियों एवं कार्यप्रणाली की जानकारी हासिल की। अध्ययन दल के सदस्यों ने राज्य सरकार द्वारा विश्व बैंक के सहयोग से संचालित जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के तहत गठित स्व-सहायता समूहों, ग्राम उत्थान समितियों एवं क्रॉप प्रोड्यूसर कम्पनियों के कार्य के प्रति विशेष रुचि जाहिर की।

नेपाल गरीबी निवारण कोष के कार्य प्रबंधक श्री तारा प्रसाद जोशी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश के भ्रमण पर आये ग्यारह सदस्यीय दल ने डी.पी.आई.पी. की राज्य परियोजना इकाई में आयोजित बैठक में भाग लेकर राज्य समन्वयकों के साथ चर्चा की। डी.पी.आई.पी. के प्रभारी परियोजना समन्वयक श्री एल.एम. बेलवाल ने नेपाल के अध्ययन दल का स्वागत करते हुए दल को राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना सहित डी.पी.आई.पी. एवं एम.पी.आर.एल.पी. एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों की जानकारी भी दी।

डी.पी.आई.पी. परियोजना के प्रजेंटेशन में बताया गया कि प्रथम चरण के सफल क्रियान्वयन के पश्चात द्वितीय चरण 14 जिलों के लगभग पाँच हजार गाँवों में संचालित किया जा रहा है। स्व-सहायता समूह आधारित द्वितीय चरण में महिलाओं के 30 हजार स्व-सहायता समूहों का गठन कर 4 हजार 500 ग्राम उत्थान समितियों का गठन किया जायेगा। द्वितीय चरण में लगभग 528 करोड़ रुपये व्यय होंगे। द्वितीय चरण में ग्रामीण गरीबों को स्थाई आजीविका साधन के लिए उनकी क्षमतावर्द्धन कर उन्हें सशक्त स्व-सहायता समूह में संगठित किया जायेगा।

प्रजेंटेशन में बताया गया कि एक अभिनव पहल के तहत डी.पी.आई.पी. द्वारा 17 प्रोड्यूसर कम्पनियां गठित की गई हैं, जिनमें 42 हजार से अधिक शेयर होल्डर हैं। इनमें से 14 क्रॉप प्रोड्यूसर कम्पनियां हैं जो छोटे और सीमांत किसानों द्वारा गठित की गई हैं। इनमें 10 प्रोड्यूसर कम्पनियां रिस्पांसिबल सोया कार्यक्रम से जुड़ी हैं, जिन्हें प्रति वर्ष 2 से 3 करोड़ रुपये प्राप्त हो रहा है। योजनाओं के साथ कन्जर्वेस के तहत 116 स्व-सहायता समूहों द्वारा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत 8.95 करोड़ रुपयों के 440 कार्य हाथ में लिए गये हैं। इसी प्रकार 47 स्व-सहायता समूह मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं।

नेपाल गरीबी निवारण कोष

नेपाल गरीबी निवारण कोष के कार्य प्रबंधक श्री तारा प्रसाद जोशी ने बताया कि प्रथम चरण में छह जिलों में प्रारम्भ किया गया गरीबी निवारण कोष अब नेपाल के 40 जिलों में संचालित किया जा रहा है। कोष के तहत कम्युनिटी आर्गनाइजेशन को सीधे राशि उपलब्ध कराई जाती है, जिसके जरिये समूहों को राशि प्राप्त होती है। गरीबी निवारण कोष द्वारा आय मूलक गतिविधियों के लिए समूहों को राशि दी जाती है, जिनकी सदस्य संख्या 30 तक होती है। गरीबी निवारण कोष का अभी द्वितीय चरण चल रहा है तथा आगामी 2012 के बाद तृतीय चरण प्रारम्भ होगा।

दल के सदस्यों ने डी.पी.आई.पी. द्वारा मध्यप्रदेश माध्यम से निर्मित लघु फिल्मों का अवलोकन किया। डी.पी.आई.पी. परियोजना की ओर श्री रमन वाधवा ने प्रजेंटेशन दिया। दल के सदस्य बाद में दो अलग-अलग टीम में विभक्त होकर शिवपुरी, गुना और राजगढ़ जिले के भ्रमण के लिए रवाना हो गये।

नेपाल के गरीबी निवारण कोष को मध्यप्रदेश के एक्सपोजर भ्रमण पर आये दल के प्रभारी श्री तारा प्रसाद जोशी ने कहा कि म.प्र. में डी.पी.आई.पी. परियोजना के काम और अच्छी कार्य पद्धति (Best Practices) देखकर उनकी टीम को काफी सीखने को मिला है। इस भ्रमण से सीख लेकर नेपाल में समूहों को मार्केट लिंकेज कराने एवं बैंकेबल बनाने की दिशा में प्रयास किये जायेंगे। नेपाल के कम्युनिटी आर्गनाइजेशन को कम्पनी के रूप में फेडरेड करने पर भी विचार किया जायेगा। म.प्र. डी.पी.आई.पी. परियोजना में विभिन्न विभागों के साथ कन्जर्वेंस से किये जा रहे काम से भी उनकी टीम को प्रेरणा मिली है। द्वितीय चरण में गठित होन वाले स्व-सहायता समूहों में शत-प्रतिशत महिला सदस्यों का होना उपलब्धि का विषय है। गाँवों में महिलाओं के मोबलाइजेशन का काम, समूहों द्वारा पंचसूत्र अपनाकर काम करने, प्रभावी सी.आर.पी. की अवधारणा, प्रोड्यूसर कम्पनियों में संचालक मंडल के रूप में शामिल सदस्य समहित समूह के सदस्य होना, कम्पनी से जुड़कर किसानों के समय और धन की बचत जैसे बिन्दुओं से भी उनकी टीम काफी प्रभावित हुई है।

श्री तारा प्रसाद जोशी ने बताया कि नेपाल में गरीबी निवारण कोष से राशि सीधे गरीबों के कम्युनिटी आर्गनाइजेशन को जाती है। गरीबी निवारण कोष के क्रियान्वयन में गरीबों को लक्षित कर आमदनीमूलक गतिविधियों, क्षमतावर्द्धन सामुदायिक अधो-संरचना विकास, रोजगार सृजन, रिवाल्विंग कोष, पारदर्शिता के लिए सूचनापाटी का प्रदर्शन, समुदाय की मांग आधारित कार्यक्रम, सामुदायिक संरक्षण के मुद्दों आदि को समाहित किया गया है। कमोबेश म.प्र. डी.पी.आई.पी. के प्रथम चरण में इन्हीं बिन्दुओं की प्रमुख रणनीति रही है।

नेपाल में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नेपाल गरीबी निवारण कोष एक एक्ट के तहत संचालित किया जा रहा है। कोष में उपाध्यक्ष सहित 12 सदस्यीय बोर्ड में प्रोफेशनल को शामिल किया गया है। सन् 2004 से संचालित गरीबी उन्मूलन कोष के प्रभावात्मक सर्वे में यह निष्कर्ष सामने आये हैं कि आमदनी में 19 प्रतिशत वृद्धि परिलक्षित हुई है। सामुदायिक सशक्तिकरण हुआ है तथा काम की तलाश में विदेशों में पलायन करने वाले लोग वापस लौटने लगे हैं। नेपाल में भी युवाओं के लिए कौशल आधारित प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं। कोष के जरिये संचालित गतिविधियों में लगभग 73 प्रतिशत महिलाएँ शामिल हैं, जबकि नियमानुसार 50 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। वहां अधोसंरचना विकास पर समुचित ध्यान दिया जा रहा है। नेपाल में गरीबी निवारण कोष का तृतीय चरण आगामी 2012 के बाद प्रारंभ होगा।

नेपाल टीम के अन्य सदस्यों ने भी राजगढ़, गुना और शिवपुरी जिलों के गाँवों के भ्रमण के अपने अनुभव और सीख प्रस्तुत की। दल के सदस्यों ने प्रोड्यूसर कम्पनियों और उनके द्वारा प्रारम्भ आउटलेट्स की उपयोगिता के बारे में फीड बैक भी लिया।

(लेखक उपसंचालक जनसंपर्क हैं।)